

Participants : [Rawat Prof. Rasa Singh](#)

an>

Title: Need to review the policy framed for Special Economic Zones.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा कि देश में उदारीकरण के नाम पर विभिन्न राज्यों में स्पेशल इकोनामिक जोन्स के तहत किसानों की हजारों हैक्टेयर उपजाऊ जमीन ली जा रही है और उसे देशी या विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिया जा रहा है। परन्तु किसानों की उपजाऊ जमीन चली जाने के कारण जहां अन्न के उत्पादन में कमी आ रही है, वहीं किसानों को उस जमीन का बाजार भाव से पूरा मुआवजा भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके साथ-साथ जमीन की लीज भी किसानों के नाम न करके, सरकार या खरीदने वालों के नाम से की जा रही है। परिणामस्वरूप किसानों में बड़ा असंतोह व्याप्त हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि उनकी इस हालत के प्रकरण पर वह पुनः विचार करे और उनकी उपजाऊ भूमि न ली जाये। अगर अनुपजाऊ या बंजर भूमि फ़ैक्टरी लगाने के लिए ली जानी है, तो वह ली जाये। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना है कि वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और जिन किसानों की भूमि ली जा रही है, उसकी लीज उनके नाम पर होनी चाहिए।